डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : माननीय महोदया, मैं आपसे विशेष उल्लेख के अन्तर्गत बोलने की अनुमति चाहती हूं।

उपसभापति : क्या चीज है, बोलिए।

Security for people of Jammu and Kashmir

डा. प्रभा ठाकुर : माननीय उपसभापति महोदया, आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की इसके लिए धन्यवाद। मैंने 15 तारीख को विशेष उल्लेख के अन्तर्गत अपना निवेदन प्रस्तुत कर रखा था और 16 तारीख को मुझे यह स्लिप प्राप्त हुई ...(**व्यवधान**)....

उपसभापति : अपनी बात कहिए, आपने क्या किया था, वह तो हो गया।

डा. प्रभा ठाकुर: महोदया, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा के संदर्भ में, मैंने 15 तारीख को विशेष उल्लेख पर बोलने की अनुमति चाही थी। जम्मू के निकट कासिम नगर में गत शनिवार रात 13 जुलाई को घटित घटना में 29 निर्दोष ग्रामीणों की निर्मम हत्या की गई। इसकी जितनी भी निन्दा की जाए कम है। केन्द्रीय सरकार ने भी इस अमानवीय हादसे की कड़ी निन्दा की है तथा हमेशा की तरह कठोर कार्यवाही करने की बात भी दुहराई है। कुछ ही सप्ताह पूर्व जम्मू क्षेत्र के कालूचक ग्राम में आतंकवादियों के हमले में हमारे जांबाज़ सैनिकों के अनेकों परिजनों ने अपने प्राण गंवाए तब भी केन्द्रीय सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने तथा आतंकवादी संगठनों से सख्ती से निपटने के दावे किए थे। इस घृणित और नृशंस हादसे ने इस सरकार के इन सभी दावों को झूठा तथा खोखला प्रमाणित किया है। बल्कि हो यह रहा है कि सरकार जितनी कठोर कार्यवाही और सुरक्षा व्यवस्था की घोषणाएं करती है, जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के निर्दोष नागरिक उतने ही आतंकवाद के अधिक शिकार होते जा रहे हैं। इस ताजा जघन्य कांड ने पुनः जम्मू-कश्मीर के बेबस नागरिकों को केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा दिए जाने तथा सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने के दावों को बिलकुल निराधार प्रमाणित करते हुए सरकार के दावों और इरादों को चुनौती दी है। पाक के आतंकवादी संगठनों पर आरोप लगाकर या पाकिस्तान पर बार-बार आरोप लगाकर, केन्द्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। देश की जनता और यह सदन, सरकार से जानना चाहता है कि यह सरकार बेकसूर कश्मीरियों की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है और क्या सचमुच गंभीर है?

उपसभापति : आपको इसीलिए अनुमति दी है, we are going to have a full-fledged discussion on Jammu and Kashmir situation. That is why your Special Mention was not accepted. But as we have time today, I allowed it. It is a very serious matter and the House is going to have a full-fledged discussion.

Now, since there is no other business now, can we take up the Private Members' Business now? Or, if the House so agrees, either we meet at 2 o' clock and advance the time of the Private Members' Business or I adjourn the House till 2.30 p.m. I leave it to the House..

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Madam, you adjourn the House till 2.30 p.m.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Does it mean that the Government has no Business?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You should have all given more Special Mentions.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Madam, this point should be noted by the hon. Minister of State for Parliamentary Affairs, because he had always been saying that the Opposition had not been cooperating with the Government in clearing the pending Business. We are now in a situation where the Government has no Business to be transacted in the House. ...*(Interruptions)*... We had facilitated a situation whereby the Government could have brought some Business.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): We could have had more Special Mentions. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, that is what I am saying. I could have allowed more Special Mentions. Actually, I should also be blamed, to some extent, because I finished the Government Business so fast the other day that there is nothing left.

The House is adjourned till 2.30 p.m. for lunch.

The House then adjourned for lunch at thirty-six minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-one minutes past

two of the clock, [THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY) In the Chair]

PRIVATE MEMBERS' BILLS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Dr. C. Narayana Reddy; not here. Shrimati S.G. Indira; not here. Shri K.B. Krishna Murthy.